भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1948

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर उपरिपुल

1948. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-66 पर केसरवल जंक्शन से वेरणा जंक्शन तक प्रस्तावित उपरिपुल निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पिरना जंक्शन को परियोजना के दायरे में शामिल किया गया है या वेरणा में बाद के जंक्शनों या क्रॉसिंग पर यातायात को सुगम बनाने के लिए उपरिपुल का और विस्तार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरिपुल परियोजना शुरू करने में प्रशासनिक, वित्तीय या पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी बाधाओं सहित विलंब के क्या कारण हैं, यदि कोई हों;

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत, निधि आवंटन और परियोजना के पूरा होने की संशोधित समय-सीमा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना में यातायात प्रवाह संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वेरणा-कैंसुआलिम जंक्शन और वेरणा-उतोरदा जंक्शन पर उपरिपुल के माध्यम से यातायात की भीड़ को कम करने के प्रावधान शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मडगांव-पणजी राजमार्ग पर यात्रियों के समक्ष लगातार आ रही यातायात की भीड़ कम करने हेतु परियोजना में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर केसरवल जंक्शन से वेरणा जंक्शन तक प्रस्तावित फ्लाईओवर, गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के किमी 536.800 से किमी 543.450 तक चार लेन निर्माण हेतु स्वीकृत परियोजना का हिस्सा है। सिविल निर्माण कार्य 24.03.2025 को 2 वर्ष की निर्माण अवधि के साथ सौंपा गया है।

(ख) पिरनी जंक्शन के दोनों तरफ सर्विस रोड सहित एक एट-ग्रेड जंक्शन के रूप में विकसित करने को स्वीकृत परियोजना के दायरे में शामिल किया गया है।

(ग) निर्माण कार्य शुरू करने में कोई देरी नहीं हुई है और संविदाकार के दायित्वों के पूरा होने और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) सौंपने के संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की तिथि अधिसूचित की गई है।

(घ) इस परियोजना को 398.25 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल पूंजीगत लागत के साथ स्वीकृत किया गया है, जिसकी पूर्णता अवधि नियत तिथि की घोषणा के बाद दो वर्ष की होगी। निधियां परियोजना-वार नहीं अपितु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी-वार आवंटित की जाती है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान गोवा राज्य के लिए 344 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ङ) परियोजना के कार्य-क्षेत्र में कैसुआलिम जंक्शन और उतोरदा जंक्शन से लगभग 300 मीटर दूर मडगांव बाईपास के आरंभ में वाहन अंडरपास (वीयूपी) का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त, केसरवल जंक्शन से मडगांव बाईपास के आरंभ तक 6.65 किलोमीटर की पूरी परियोजना अवधि में सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड प्रस्तावित हैं ताकि स्थानीय वाहनों की आवाजाही सुगम हो और यातायात की भीड़भाड़ कम हो, जिससे यातायात प्रवाह और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

(च) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और डेटा लेक, भूमि राशि पोर्टल (भूमि अधिग्रहण हेतु) के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, लंबित संविदात्मक मुद्दों के समाधान और परियोजनाओं का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियों (गोवा लोक निर्माण विभाग) के अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा की जाती है।

*****